नईदुनिया

संपादकीय

पेपर लीक माफिया अब नहीं बचेगा
तीन महीने में फैसला सुनाएंगे चार फास्ट ट्रैक कोर्ट

मध्यप्रदेश *में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह, नकल माफिया और इम्पर्सोनेशन कराने वाले आरोपियों के मामलों की सुनवाई वर्षों तक लंबित नहीं रहेगी। राज्य में पहली बार चार विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए गए हैं, जो ऐसे मामलों का फैसला तीन महीने के भीतर सुनाने का लक्ष्य लेकर काम करेंगे।*

लोक परीक्षाएं (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के तहत उठाया गया यह कदम केवल दोषियों को सजा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने और युवाओं का भरोसा मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशों की अदालतों को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नामित किया है। इन अदालतों में पेपर लीक, नकल और इम्पर्सोनेशन से जुड़े मामलों की प्राथमिकता से सुनवाई होगी। निर्देश दिए गए हैं कि चार्जशीट दाखिल होने की तारीख से तीन महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जाए, ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित रहने की स्थिति समाप्त हो। पिछले कुछ वर्षों में व्यापम से लेकर विभिन्न भर्ती परीक्षाओं तक प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा में नकल और दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलाने जैसे मामलों ने लाखों अभ्यर्थियों का विश्वास कमजोर किया है। सबसे अधिक नुकसान उन युवाओं को हुआ, जिन्होंने कठिन मेहनत से तैयारी की, लेकिन परीक्षा व्यवस्था की खामियों का खामियाजा भुगता।

नए कानून में दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। प्रश्नपत्र लीक कराने वालों को दस वर्ष तक की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इम्पर्सोनेशन और नकल में सहयोग करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई होगी। दोष सिद्ध होने पर सरकारी नौकरियों से प्रतिबंध जैसे प्रावधान भी लागू किए जा सकते हैं।

हालांकि, केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होगा। पेपर लीक के मामले अब तकनीकी रूप ले चुके हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप, साइबर नेटवर्क और संगठित गिरोहों की भूमिका की प्रभावी जांच के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों को आधुनिक तकनीक से लैस करना होगा। समय पर मजबूत चार्जशीट और ठोस साक्ष्य ही इन अदालतों की सफलता तय करेंगे। यदि यह व्यवस्था प्रभावी साबित होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ युवाओं को मिलेगा। परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, अभ्यर्थियों का विश्वास लौटेगा और भर्ती एजेंसियों पर भी निष्पक्ष एवं सुरक्षित परीक्षा कराने का दबाव बनेगा। समयबद्ध न्याय का यही संदेश अपराधियों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी होगा। परीक्षा व्यवस्था किसी भी राज्य की प्रतिभा और भविष्य की नींव होती है।

यदि इस व्यवस्था में सेंध लगती है तो सबसे बड़ा नुकसान योग्य और मेहनती युवाओं का होता है। ऐसे में फास्ट ट्रैक कोर्ट की यह पहल केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा और रोजगार व्यवस्था में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आजकल

वंदे मातरम् का अपमान अपराध

राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के सम्मान को कानूनी संरक्षण देने के उद्देश्य से संसद के निचले सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। सरकार का कहना है कि यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। प्रस्तावित कानून के अनुसार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम् का अपमान करने, उसके गायन में बाधा डालने या जानबूझकर उसका उपहास उड़ाने पर तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान होगा।

गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया था। अब तक राष्ट्रीय गान जन गण मन के सम्मान से संबंधित कानूनी प्रावधान मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रीय गीत के लिए अलग कानून नहीं था। सरकार का तर्क है कि स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत ने देशवासियों को प्रेरित किया, इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा आवश्यक है।

विधेयक को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी शुरू हो गई है। कुछ सांसदों ने इसका स्वागत किया, जबकि कुछ ने अपमान की परिभाषा और संभावित दुरुपयोग पर सवाल उठाए। सरकार ने स्पष्ट किया कि कानून का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान को मजबूत करना है।

विधेयक में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के गायन को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों को इसके इतिहास और महत्व से परिचित कराने का भी प्रस्ताव है। सरकार का मानना है कि कानून के साथ जनजागरूकता भी आवश्यक है।

वंदे मातरम्, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित, स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणास्रोत रहा है। अब यह देखना होगा कि संसद में यह विधेयक किस स्वरूप में पारित होता है और व्यवहार में इसका प्रभाव कितना पड़ता है। किसी भी कानून की सफलता अंततः नागरिकों की जागरूकता और स्वैच्छिक सम्मान पर ही निर्भर करती है।

परिवार में समय देना और संवाद बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता

मातृत्व और परिवार के मूल्यों पर गहन चिंतन, युगानुकूल मातृत्व और हमारी सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसमें देशभर से आई महिलाओं ने अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपने विचार व्यक्त किए। इसका उद्देश्य बदलते सामाजिक परिवेश में भारतीय परिवार और मातृत्व की भूमिका पर नए सिरे से विचार करना था। कार्यक्रम का आयोजन विश्वमंगल सभा द्वारा उत्तर भारत के राष्ट्रीय प्रबोधन के अंतर्गत 23 और 24 जुलाई को किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 900 से अधिक प्रबुद्ध मातृशक्ति उपस्थित रही।

मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि परिवार में समय देना और संवाद बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चों की आवश्यकता है कि माता-पिता उन्हें समय दें, उनकी बात सुनें और उनके साथ बैठें। आज के तेज रफ्तार जीवन में, जब माता-पिता दोनों काम में व्यस्त हैं, तब बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताना और भी जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं, इसलिए माता-पिता को स्वयं आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए।

डॉ. भागवत ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे उपदेश से अधिक आचरण से सीखते हैं। इसलिए घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, जहां प्रेम, सम्मान और अनुशासन तीनों हों। उन्होंने कहा कि माता-पिता का ज्ञान भी निरंतर बढ़ना आवश्यक है, ताकि वे बच्चों को सही दिशा दे सकें। आज के समय में जानकारी बहुत है, लेकिन संस्कारों की कमी दिखाई दे रही है। इसलिए माता-पिता को स्वयं सीखना होगा और फिर बच्चों को सिखाना होगा।

मातृत्व केवल जन्म देने का नाम नहीं है। मातृत्व एक साधना और जिम्मेदारी है, जो समाज की नींव

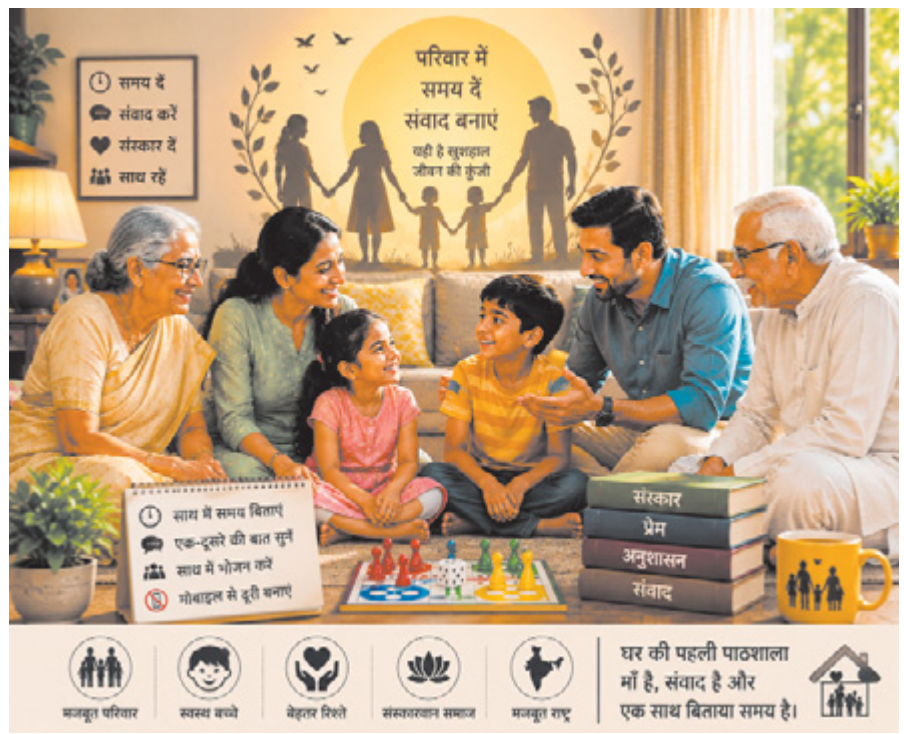

बनाती है। जब माँ सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है और जब परिवार सशक्त होता है तो समाज और राष्ट्र मजबूत बनते हैं। इसलिए माताओं को शिक्षित करना, आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें मानसिक सहयोग देना आज के समय की मांग है।

तकनीक और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव से बच्चों और माता-पिता के बीच दूरी बढ़ रही है। पहले घर में एक साथ बैठकर बातचीत होती थी, कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन अब हर कोई अपने मोबाइल में व्यस्त है। इससे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इसलिए परिवार के लिए समय निकालना जरूरी है। साथ में भोजन करना, घूमना और त्योहार मनाना जैसी छोटी-छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं।

भारतीय संस्कृति में मातृत्व को हमेशा सर्वोच्च स्थान मिला है। माँ को पहली गुरु माना गया है। लेकिन आज की पीढ़ी पर पश्चिमी जीवनशैली का प्रभाव बढ़ने से परिवार की संरचना बदल रही है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ऐसे में माताओं की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्हें घर और बाहर, दोनों जगह संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए समाज को भी माताओं का सम्मान करना चाहिए और उनके योगदान को उचित महत्व देना चाहिए।

कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। कई महिलाओं ने बताया कि उन्होंने नौकरी और परिवार दोनों की जिम्मेदारियां निभाते हुए बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। कुछ ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए उन्होंने स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना शुरू किया। कुछ ने घर में सप्ताह में एक दिन 'नो स्क्रीन डे' रखा, जिसमें पूरा परिवार साथ समय बिताता है। इन अनुभवों ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया।

इस तरह की बैठकों का उद्देश्य केवल चर्चा करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाना है। अगले चरण में विभिन्न राज्यों में मातृशक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां स्थानीय स्तर पर महिलाओं को जोड़कर परिवार और समाज निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी मातृत्व और परिवार के महत्व पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

राष्ट्र निर्माण ईंट और पत्थरों से नहीं, बल्कि संस्कारों से होता है। संस्कारों की पहली पाठशाला घर है और घर की पहली शिक्षिका माँ है। यदि हमें एक मजबूत और चरित्रवान भारत बनाना है तो मातृत्व को सम्मान देना होगा, परिवार को समय देना होगा और बच्चों के साथ संवाद की परंपरा को फिर से जीवित करना होगा। समस्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हों, उनका समाधान परिवार से ही शुरू होता है और परिवार की धुरी मातृत्व है। यदि मातृत्व को समयानुकूल नई ऊर्जा और समझ के साथ सशक्त किया जाए तो आने वाली पीढ़ी केवल सफल ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

भोपाल और जबलपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स की नई उड़ान 150 करोड़ के निवेश से बदलेगी तस्वीर

मध्यप्रदेश अब आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। भोपाल और जबलपुर में बने आईटी पार्क अब केवल सॉफ्टवेयर के केंद्र नहीं रहे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब के रूप में उभर रहे हैं। राज्य सरकार की नई नीति और निवेशकों के भरोसे के चलते यहां भोपाल में 18 और जबलपुर में 40 कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। इन कंपनियों ने मिलकर करीब 150 करोड़ रुपये का निवेश किया है और आने वाले समय में हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में 204 एकड़ भूमि पर बना आईटी पार्क अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर के रूप में विकसित हो चुका है। यहां 50 एकड़ भूमि विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए आरक्षित की गई है, जिसमें अब तक 114 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 48 कंपनियों ने अपना उत्पादन भी शुरू कर दिया है। जबलपुर में भी 88 कंपनियों को जमीन आवंटित की गई है और यहां 40 से अधिक भूखंडों पर निर्माण कार्य चल रहा है। पांच एकड़ क्षेत्र में एक लाख वर्गफुट का आईटी भवन बनकर तैयार है, जिसे 12 कंपनियों को किराये पर दिया जा चुका है। इनमें सरसटेक, ग्लोबल टेक्नोट्रस्ट और आरटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो सॉफ्टवेयर के साथ-साथ हार्डवेयर उत्पादन का कार्य भी कर रही हैं।

राज्य सरकार ने 2021-22 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी और 2025 तक 1300 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। जबलपुर आईटी पार्क में 35 हजार वर्गफुट का नया भवन भी तैयार किया जा रहा है, ताकि और कंपनियों को स्थान मिल सके। भोपाल और जबलपुर, दोनों जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने विशेष फोकस किया है। बिजली, पानी, सड़क और इंटरनेट की सुविधा के साथ सुरक्षा तथा परिवहन व्यवस्था भी बेहतर की गई है। इस पूरे बदलाव की नींव फरवरी 2027 में आईकॉमोस

की रिपोर्ट के बाद रखी गई थी, जिसमें भोपाल को सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ तकनीकी विकास के लिए भी उपयुक्त बताया गया था। इसके बाद सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र और प्लग एंड प्ले मॉडल पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की थी कि मध्यप्रदेश को देश का अगला इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाया जाएगा और इसके लिए भोपाल, जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर को भी जोड़ा जाएगा।

निवेशकों का कहना है कि मध्यप्रदेश में जमीन की उपलब्धता, श्रमशक्ति और सरकारी सहयोग तीनों एक साथ मिल रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की कंपनियां भी यहां निवेश और विस्तार में रुचि दिखा रही हैं। कुछ कंपनियों ने पहले ही प्रोटोटाइप और असेंबली यूनिट शुरू कर दी हैं और अगले दो वर्षों में पूर्ण स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की योजना है। इससे न केवल आईटी क्षेत्र को बल मिलेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, मोबाइल कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर से जुड़े उद्योग भी यहां विकसित होंगे।

युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अब उन्हें रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। भोपाल और जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां छात्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार और निजी कंपनियों के बीच एमओयू भी हुए हैं, ताकि कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप को बढ़ावा मिल सके। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती कुशल मानव संसाधन की है, लेकिन सरकार ने इसके लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। दूसरी चुनौती वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने की है। इसके लिए केंद्र सरकार की पीएलआई योजना का लाभ उठाया जा रहा है और निर्यात के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित करने पर काम चल रहा है। भोपाल और जबलपुर का यह नया अध्याय मध्यप्रदेश की आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। 150 करोड़ रुपये का निवेश अभी केवल शुरुआत है। आने वाले पांच वर्षों में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। जब यहां निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद देश के साथ-साथ विदेशों में भी पहुंचेंगे, तब मध्यप्रदेश को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मानचित्र पर एक मजबूत पहचान मिलेगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

इस्तीफे से नहीं, सुधार से लौटेगा विश्वास

लोकतंत्र में किसी मंत्री का इस्तीफा केवल एक राजनीतिक घटना नहीं होता, बल्कि वह शासन व्यवस्था की जवाबदेही और जनता के विश्वास की भी परीक्षा बन जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने भी यही सवाल खड़ा किया है कि क्या केवल पद छोड़ देने से शिक्षा व्यवस्था पर लगे अविश्वास के दाग मिट जाएंगे, या फिर यह व्यापक सुधारों की शुरुआत बनेगा।

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। लाखों विद्यार्थी वर्षों तक कठिन परिश्रम कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि प्रश्नपत्र लीक हों, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठें या अनियमितताओं की खबरें सामने आएं, तो सबसे बड़ी चोट विद्यार्थियों के मनोबल और व्यवस्था पर उनके भरोसे को लगती है। यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं, बल्कि पूरे भविष्य की चिंता का विषय बन जाता है।

नीट-यूजी परीक्षा विवाद के बाद देशभर में छात्रों का आक्रोश इसी चिंता का परिणाम था। आंदोलन की शुरुआत भले ही पेपर लीक के विरोध से हुई हो, लेकिन धीरे-धीरे यह पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह परीक्षा प्रणाली की मांग में बदल गया। सरकार ने जांच कराई, सुधारों की घोषणा की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। इसके बावजूद जनभावना यही रही कि जवाबदेही तय किए बिना विश्वास बहाल नहीं हो सकता।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी नैतिक जवाबदेही का प्रतीक माना जा सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह संदेश महत्वपूर्ण है कि यदि किसी विभाग में गंभीर चूक होती है तो उसकी जिम्मेदारी शीर्ष नेतृत्व को भी स्वीकार करनी चाहिए। इससे शासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होता है। हालांकि केवल इस्तीफा ही समाधान नहीं है। यदि व्यवस्था की कमजोरियां जस की तस बनी रहें, तो नए चेहरे भी पुराने संकटों को नहीं रोक पाएंगे।

आज सबसे बड़ी आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को तकनीकी रूप से अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की है। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, डिजिटल निगरानी, त्वरित जांच, दोषियों को कठोर दंड और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित किए बिना ऐसे विवाद दोबारा सामने आ सकते हैं।

यह पूरा घटनाक्रम एक सकारात्मक संदेश भी देता है कि देश का युवा अपने अधिकारों और भविष्य के प्रति सजग है। लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनाव में नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने में निहित होती है। इसलिए इस इस्तीफे को किसी राजनीतिक जीत या हार के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का अवसर माना जाना चाहिए। यदि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही की नई संस्कृति विकसित होती है, तभी यह कदम वास्तव में सार्थक सिद्ध होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

84 महादेव दर्शन यात्रा

उज्जैन के 84 महादेव (भाग-40)

कुण्डेश्वर महादेव : जहां भैरव-पूजन से प्राप्त होती है मातृकृपा की अक्षय निधि

डॉ. नवीन आनंद जोशी

उज्जयिनी की पावन भूमि केवल ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के कारण ही विश्वविख्यात नहीं है, बल्कि यहां स्थित चौरासी महादेवों की परंपरा भी सनातन संस्कृति की अनुपम आध्यात्मिक धरोहर है। प्रत्येक शिवलिंग अपने भीतर एक दिव्य इतिहास, एक जीवनोपयोगी संदेश और धर्म के किसी गूढ़ सिद्धांत को समेटे हुए है। अंकपात मार्ग पर संदीपनी आश्रम के समीप स्थित कुण्डेश्वर महादेव भी ऐसा ही एक सिद्ध तीर्थ है, जहां शिव, शक्ति और भैरव-तत्त्व का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यह केवल उपासना का स्थान नहीं, बल्कि मातृशक्ति, सेवाभाव और कर्तव्यनिष्ठा के सनातन आदर्श का जीवंत प्रतीक है।

स्कन्दपुराण के अवन्ती खण्ड में वर्णित कथा के अनुसार एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से अपने पुत्र वीरक की कुशल पूछी। भगवान शिव ने बताया कि वीरक महाकाल वन में तपस्या कर रहा है। पुत्र-दर्शन की उत्कट इच्छा से माता स्वयं भगवान शिव के साथ नंदी पर आरूढ़ होकर महाकाल वन की ओर प्रस्थान करती हैं। मार्ग में एक पर्वत पर माता को भय का अनुभव होता है। तब भगवान शिव उन्हें अपने परम विश्वस्त गण कुण्ड की देखरेख में छोड़कर आगे चले जाते हैं।समय बीतता गया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी भगवान शिव वापस नहीं लौटे। माता पार्वती की व्याकुलता बढ़ती गई। कुण्ड गण अपनी पूरी निष्ठा और सेवा के बावजूद उन्हें शिव-दर्शन नहीं करा सका। क्षणिक क्रोध में माता ने उसे मनुष्य लोक

में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। माता का हृदय करुणा से भर उठा और उन्होंने उसी श्राप को कल्याणकारी वरदान में परिवर्तित करते हुए आदेश दिया कि कुण्ड महाकाल वन में भैरव स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर उस दिव्य शिवलिंग की सेवा करे, जो आगे चलकर कुण्डेश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो श्रद्धालु भैरव का सम्मान करते हुए कुण्डेश्वर महादेव के दर्शन करेगा, उसे शिवकृपा के साथ मातृकृपा का भी अक्षय फल प्राप्त होगा।

यह प्रसंग सनातन दर्शन का अत्यंत सूक्ष्म संदेश देता है। माता पार्वती का क्रोध भी अंततः लोककल्याण का कारण बनता है और एक निष्कपट सेवक अमरत्व प्राप्त करता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में भैरव को केवल क्षेत्रपाल या रक्षक नहीं माना गया, बल्कि वे अनुशासन, सेवा, निष्ठा और आज्ञापालन के प्रतीक भी हैं। शिवालयों में भैरव की पूजा का महत्व इसी आध्यात्मिक सत्य की ओर संकेत करता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अहंकार से नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा से प्रशस्त होता है।

यह कथा हमें 'मातृ देवो भव' के वैदिक संदेश की भी स्मृति कराती है। भारतीय संस्कृति में माता को प्रथम गुरु और प्रथम देवता माना गया है। मनुष्य के जीवन में ज्ञान, संस्कार, धैर्य और करुणा का प्रथम बीजारोपण माता ही करती है। इसलिए हमारे यहां मातृआशीर्वाद को किसी भी सांसारिक उपलब्धि से अधिक मूल्यवान माना गया है।आज का युग विज्ञान, तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग है। संसाधनों की कमी नहीं है, किंतु मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास का संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय कुण्डेश्वर महादेव की कथा अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होती है। एक विद्यार्थी के पास उत्कृष्ट पुस्तकें, आधुनिक तकनीक और श्रेष्ठ कोचिंग हो सकती है, किंतु परीक्षा के लिए घर से निकलते समय जब वह अपनी माता के चरण स्पर्श करता है, तब उसके भीतर जो आत्मबल जागृत होता है, वह किसी तकनीक से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार किसी चिकित्सक, सैनिक, अधिकारी या उद्यमी के जीवन में कठिन निर्णय के क्षणों में माता का विश्वास और आशीर्वाद उसे ऐसी मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है, जो अनेक बाहरी साधनों से भी संभव नहीं होती।

कुण्डेश्वर महादेव का संदेश यह भी है कि सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। कुण्ड गण तत्काल अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सका, किंतु उसने सेवा और निष्ठा का मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः वही सेवाभाव उसे भैरव के दिव्य पद तक ले गया। आज के समाज में भी यही शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। परिणामों की अधीर प्रतीक्षा करने के बजाय यदि मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वरार्पण बुद्धि से निभाए, तो सफलता समय आने पर स्वयं उसके द्वार पर आती है। उज्जैन के चौरासी महादेव केवल धार्मिक पर्यटन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के जीवंत विश्वविद्यालय हैं। प्रत्येक शिवलिंग जीवन का एक नया अध्याय सिखाता है। कुण्डेश्वर महादेव हमें बताते हैं कि मातृभक्ति, अनुशासन, सेवाभाव और शिवनिष्ठा—ये चारों मिलकर मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाते हैं। भैरव-पूजन का वास्तविक अर्थ भय नहीं, बल्कि धर्म की मर्यादा का पालन है; शिव-भक्ति का अर्थ केवल जलाभिषेक नहीं, बल्कि निष्काम सेवा है; और मातृकृपा का अर्थ केवल आशीर्वचन नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवन के प्रत्येक संघर्ष में मनुष्य को अडिग बनाए रखती है।इसीलिए कुण्डेश्वर महादेव का यह पावन तीर्थ आज भी श्रद्धालुओं को केवल दर्शन का नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन का संदेश देता है। जो मनुष्य माता-पिता का सम्मान करता है, सेवा को साधना मानता है और शिव के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, उसके लिए प्रत्येक कठिनाई अंततः कल्याण का मार्ग बन जाती है। यही कुण्डेश्वर महादेव की कथा का शाश्वत संदेश है और यही सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत।

क्रमशः